प्रसार भारती
आकाशवाणी शिमला
29.08.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- कैग रिपोर्ट ने खोली हिमाचल की अर्थव्यवस्था की पोल–कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज के सहारे प्रदेश सरकार।
- राज्य में स्थापित सीमेंट संयंत्रों और औद्योगिक इकाईयों द्वारा किए जा रहे उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई करेगी सरकार।
- प्रदेश में नव गठित नगर निगमों व स्थानीय निकायों में अब दो साल के भीतर होंगे चुनाव–संबंधित संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित।
- प्रदेश में मॉनसून की मूसलाधार बारिश का क्रम जारी रहने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित।
- मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित जिलों में राहत व बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाने के दिए निर्देश।

कैग

प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान आज सदन में कैग की वर्ष 2023–24 की रिर्पोट प्रस्तुत की गई। रिर्पोट में खुलासा किया गया है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था इस समय भारी दबाव में है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकारें पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज ले रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 24 के बीच कर्जों का भुगतान भी ऋण लेकर किया गया है और कर्ज चुकाने के लिए 2019 में लोक ऋण का 52 दशमलव 9–9 फीसद हिस्सा खर्च किया गया। यह 2024 तक बढ़ कर 74 दशमलव 1–1 प्रतिशत हो गया इससे स्पष्ट है कि संसाधन जुटाने व फिजूलखर्ची पर नकेल कसने के राज्य सरकारों के दावे खोखले साबित हुए हैं। रिर्पोट में कहा गया है कि सरकार ने 14 मामलों में 7 सौ 11 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया, मगर हकीकत इसके विपरीत थी। कैग ने अपनी रिर्पोट में ओपीएस लागू करने से अर्थव्यवस्था पर पडने़ वाले दबाव का भी उल्लेख किया है।

प्रश्नकाल

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पिछले एक साल में मौजूदा सरकार ने 126 नए संस्थान खोले और अधिसूचित किए हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक दिलीप कुमार के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए संस्थान गुण दोष के आधार पर खोले जाते हैं और संस्थानों के लिए दी गई जमीनों को वापस करने का कोई विचार नहीं है। अर्की के विधायक संजय अवस्थी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार राज्य में सीमेंट संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सीएसआर के अंतर्गत आने वाली राशि परियोजना क्षेत्र में ही खर्च करें, न कि हिमाचल प्रदेश के बाहर। हर्षवर्धन चौहान ने सदन को आश्वस्त किया कि जहाँ भी खनन और पर्यावरण संबंधी उल्लंघन हो रहे हैं, विभाग उन कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इन इकाइयों के प्रबंधन के साथ एक बैठक बुलाएंगे ताकि उन्हें संबंधित विधायक और पंचायत प्रतिनिधियों के परामर्श से सीएसआर के अंतर्गत अपने लाभ का दो प्रतिशत परियोजना क्षेत्र में खर्च करने के लिए राजी किया जा सके।

उद्योग मंत्री ने स्वीकार किया कि अडानी समूह द्वारा अधिग्रहित अर्की और बागा स्थित सीमेंट संयंत्रों में रात के समय सबसे अधिक पर्यावरणीय उल्लंघन किए जा रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का सी.एस.आर. के पैसे पर बहुत कम नियंत्रण है और इस फंड का पूरा डेटा केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार खनन पट्टे और उन क्षेत्रों को मालिकों को वापस करने के मुद्दे पर विचार करेगी जहाँ चूना पत्थर के भंडार समाप्त हो गए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद नहीं होगी, सरकार पहले इस योजना के तहत पुराने मामलों का निपटारा करेगी, उसके बाद नए आवेदनों में अनुदान देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। विधायक विनोद कुमार, दीप राज, विवेक कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने ये बात कही।

विधेयक

हिमाचल प्रदेश में नव गठित नगर निगमों व स्थानीय निकायों में अब दो साल के भीतर चुनाव होंगे। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कल इस संबंध में प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 पेश किया था। इन विधेयकों को आज विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया द्वारा मतदान के लिए रखे गए इन संशोधनों को विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर जनभावना के विरुद्ध ओबीसी आरक्षण की आड़ में राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 में संशोधन के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। विपक्षी विधायकों ने कहा कि ये संशोधन विधेयक जनभावना और स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद लाये गए हैं। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की गैर मौजूदगी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को निराधार बताया।

नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार केवल चुनाव टालने के लिए इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह संशोधन सदन द्वारा पारित किया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन यह कानून की अदालत में नहीं टिक पाएगा।

मौसम

राजधानी शिमला सहित प्रदेश में मॉनसून की जोरदार वर्षा का क्रम जारी है जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किन्नौर ज़िले में भारी बारिश के चलते लिप्पा के भौडरती नाला और पेजर खड्ड में अचानक बाढ़ आने से कुछ मकानों सहित बागीचों और डोगरी को नुकसान हुआ है। भौडरती नाले के मलबे में दबे दो मज़दूरों को स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षित बचाकर लिप्पा अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये दोनों जम्मू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधर, चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा पर फंसे करीब डेढ़ सौ श्रद्धालुओं को बसों के माध्यम से जिला के जांघी से पठानकोट के लिए भेजा गया है। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा है कि मणिमहेश यात्रा के ट्रैक पर विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। इधर कुल्लू जिला के आनी उपमण्डल के पटारना गांव में भू–स्खलन की चपेट में आने से तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है जबकि एक लापता है। इस घटना में एक अन्य घायल को आनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा खादवी में बारिश और भू–स्खलन से आधार दर्जन भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केन्द्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आगामी 31 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

आज देर शाम से लेके तारीख तक प्रदेश में बारिश का दौर जो है जारी रहेगा। आज 29 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट ऊना ,कांगड़ा, मंडी ,सिरमौर यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। कल 30 अगस्त कुल्लू डिस्ट्रिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और 31 अगस्त के लिए कांगड़ा ,मंडी, सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है।बाकी डिस्ट्रिक्ट जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर है और साथ में शिमला, सोलनहै यहां पे एक दो स्थानों पे हैवी रेन फॉल भी हो सकती है। इसको देखते हुए एक दो डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। 1 और 2 तारीख को भी डिस्ट्रिक ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला ,सिरमौर, यहां पर एक दो स्थानों पर हैवी रेनफॉल हो सकती है। फिर 3 तारीख से वैदर काफी कमी आई है। अगस्त माह में पूरे प्रदेश में एवरेज सामान्य से करीबन 67प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है।

जगत नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी आज चम्बा जिले में आज भारी बारिश से प्रभावित उदयपुर, राखबग्गा सहित विभिन्न इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को पठानकोट तक तत्काल प्रभाव से निशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154–ए के तहत भरमौर चम्बा के

बीच हल्के वाहनों के परिचालन वाले हिस्सों में टैक्सियों के माध्यम से निशुल्क व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है। जगत सिंह नेगी ने चम्बा से भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग को युद्धस्तर पर बहाल करने के भी निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने कहा कि घायल श्रद्धालुओं को हैलीकॉप्टर के माध्यम से चम्बा पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने वापिस आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से संवाद कर फीडबैक भी ली। उन्होंने सरकार की तरफ से प्रभावितों को हर सम्भव सहायता का आश्वासन भी दिया।

चम्बा पहुंचा हूं, रास्ते में जो है ढेर सारे जगह जाकर विजिट किया,जहां लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। अभी जो है मेन हमारा आज का कार्यक्रम जो हैभरमौर से जो लोग उनको निकालने के लिए उसके लिए रोड़ को रिस्टोर करना है। मैं अभी जो है पैदल जा रहा हूं। 14–15 किलोमीटर तक गाड़ी जाएगी। उसके बाद में पैदल जाकर वहां पर किस तरह के जो है मतलब काम में तेजी लाई जा सकती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में काम करके सड़क को बहाल करके लोगों को वहां से निकालने का थोड़ा प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावित चम्बा, कुल्लू, लाहौल स्पिति, कांगड़ा और मण्डी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से एक बैठक की। इस दौरान राहत व पुर्नवास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने मणिमहेश यात्रा के दौरान चम्बा जिले में फंसे श्रद्धालुओं की सुरक्षित घर वापसी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश देते हुए मौसम के पुर्वानुमान के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए पुख्ता प्रबंध करने को भी कहा। उन्होंने बीमार और वृद्ध यात्रियों को हैलीकॉप्टर के माध्यम से निकालने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लाहौल स्पिति जिले के सिसु में फंसे सभी 3 सौ 80 पर्यटकों को आज शाम सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके अलावा चम्बा पठानकोट मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों जबकि कुल्लू–मण्डी राष्ट्रीय राजमार्ग–3 को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- कैग रिपोर्ट ने खोली हिमाचल की अर्थव्यवस्था की पोल–कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज के सहारे प्रदेश सरकार।
- राज्य में स्थापित सीमेंट संयंत्रों और औद्योगिक इकाईयों द्वारा किए जा रहे उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई करेगी सरकार।
- प्रदेश में नव गठित नगर निगमों व स्थानीय निकायों में अब दो साल के भीतर होंगे चुनाव–संबंधित संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित।
- प्रदेश में मॉनसून की मूसलाधार बारिश का क्रम जारी रहने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित।
- मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित जिलों में राहत व बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाने के दिए निर्देश।